

भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वदियमान चुनौतियाँ

यह एडिटरियल 12/08/2023 को 'द हट्टू' में प्रकाशित "India needs a new economic policy" लेख पर आधारित है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वदियमान चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई है।

प्रलिस के लिये: [जीडीपी](#), [मुद्रासफीति](#), [बेरोज़गारी](#), [कोवडि-19 महामारी](#), [वशिव बैंक](#), [चालू खाता घाटा](#), [अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष](#), [वनिविश](#), [उत्पादन-लकिड प्रोतसाहन \(PLI\) योजना](#), [बौद्धिक संपदा अधकिर](#)।

मेन्स के लिये: भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वदियमान चुनौतियाँ

भारत एक बड़ी और जटलि अर्थव्यवस्था है जिसके समक्ष वृद्धि और वकिस की अपनी यात्रा में कई चुनौतियाँ और अवसर मौजूद हैं। देश ने अपनी चुनौतियों का समाधान करने और अवसरों का लाभ उठाने के लिये वभिन्नि सुधार किये हैं। **1.3 बलियिन से अधकि की आबादी और 2.7 ट्रलियिन डॉलर से अधकि की जीडीपी** के साथ भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से वकिस करती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हालाँकि देश के समक्ष कई आर्थकि चुनौतियाँ भी मौजूद हैं और उनसे नपिटने के लिये कई सुधार किये गए हैं। यद भारत अपनी आर्थकि चुनौतियों को दूर कर सके और अपने आर्थकि सुधारों को बनाये रख सके तो वह 21वीं सदी में वैश्वकि नेता बनने की क्षमता रखता है।

भारत के समक्ष वदियमान आर्थकि चुनौतियाँ:

• कमज़ोर मांग:

- नमिन् आय वृद्धि, **उच्च मुद्रासफीति**, **बेरोज़गारी** और **कोवडि-19 महामारी** के प्रभाव जैसे वभिन्नि कारकों के कारण भारत में वस्तुओं और सेवाओं की मांग गतहिन् रही है या घट रही है।
- इससे अर्थव्यवस्था में **उपभोग और नविश का स्तर प्रभावति** हुआ है तथा सरकार के लिये कर राजस्व कम हो गया है।

• बेरोज़गारी:

- तीव्र आर्थकि वकिस के बावजूद **ग्रामीण और शहरी** दोनों क्षेत्रों में **बेरोज़गारी** एक गंभीर समस्या बनी हुई है।
- **कोवडि-19 महामारी** ने स्थिति को और बदतर कर दिया है, क्योंकि कई व्यवसाय बंद हो गए हैं या उनके परिचालन स्तर में कमी आई है, जिससे नौकरियों की हानि हुई है।
- **सेंटर फॉर मॉनटिरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE)** के अनुसार, अप्रैल और जुलाई 2020 के बीच 1.8 करोड़ से अधकि वेतन भोगी नौकरियाँ चली गईं।

- **अगस्त 2020 में बेरोज़गारी दर 7.4%** थी, जबकि अगस्त 2019 में यह **5.4%** रही थी।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)** रिपोर्ट के अनुसार वर्ष **2021-22 में 4.1%** की बेरोज़गारी दर दर्ज की गई।

• कमज़ोर अवसंरचना:

- भारत में **सड़क, रेलवे, बंदरगाह, बजिली, पानी और स्वच्छता** जैसे पर्याप्त अवसंरचना का अभाव है, जो इसके आर्थकि वकिस और प्रतसिपर्द्धात्मकता को बाधति करता है।

- **वशिव बैंक** के अनुसार भारत का **अवसंरचनात्मक अंतराल (infrastructure gap)** लगभग **1.5 ट्रिलियन डॉलर** के होने का अनुमान है। कमज़ोर अवसंरचना लोगों के जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।

- **भुगतान संतुलन का बगिड़ना:**

- भारत चालू खाता घाटे से लगातार जूझता रहा है, जिसका अर्थ है कि इसका **आयात इसके निर्यात से अधिक है**।
- यह वदेशी वस्तुओं और सेवाओं, विशेषकर तेल एवं सोने पर इसकी निर्भरता तथा **इसकी निम्न निर्यात प्रतिसिपर्द्धा को परलिक्षति** करता है।

- वर्ष 2022 में भारत के **निर्यात और आयात में क्रमशः 6.59% और 3.63%** की कमी आई।

- **नज्जी ऋण का उच्च स्तर:**

- आसान ऋण उपलब्धता और निम्न ब्याज दरों के कारण **भारत में नज्जी ऋण में, विशेष रूप से कॉर्पोरेट और घरेलू क्षेत्रों में, वृद्धि** देखी गई है।
- हालाँकि इससे डफ़ॉल्ट और वित्तीय अस्थिरता का खतरा भी उत्पन्न हुआ है, विशेष रूप से यदाय वृद्धि की गतिमंद हो जाए या ब्याज दरों में वृद्धि हो।

- **भारतीय रजिर्व बैंक (RBI)** के अनुसार मार्च 2020 में गैर-वित्तीय क्षेत्र का कुल ऋण सकल घरेलू उत्पाद का **167%** था, जो मार्च 2016 में **151%** रहा था।

- **असमानता:**

- भारत में आय और धन **असमानता का उच्च स्तर पाया** जाता है, जिसमें समय के साथ वृद्धि हुई है।
- 'वर्ल्ड इंकवलिटी डेटाबेस' के अनुसार, वर्ष 2019 में राष्ट्रीय आय में शीर्ष 10% आय अर्जकों की हस्सिदेदारी **56%** थी, जो वर्ष **1980 में 37%** रही थी।
- इसी तरह, वर्ष 2019 कुल धन में शीर्ष 10% धन-धारकों की हस्सिदेदारी **77%** पाई गई, जो वर्ष **2000 में 66%** रही थी।
- असमानता के उच्च स्तर से सामाजिक अशांति, राजनीतिक अस्थिरता और निम्न आर्थिक विकास जैसी स्थितियाँ बन सकती हैं।

भारत में किये गए प्रमुख आर्थिक सुधार:

- **उदारीकरण (Liberalization):**

- भारत ने उदारीकरण की अपनी प्रक्रिया वर्ष 1991 में शुरू की, जब उसे भुगतान संतुलन संकट का सामना करना पड़ा और सहायता के लिये **अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** से सहायता लेनी पड़ी।
- इन सुधारों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों—जैसे उद्योग, व्यापार, वित्त और वदेशी निवेश में **सरकारी हस्तक्षेप एवं वनियमन को कम** करना था।
- सुधारों में **लाइसेंस-परमिट-कोटा प्रणाली** को समाप्त करना भी शामिल था, जो नज्जी कंपनियों के प्रवेश और वस्तितार को प्रतबिधति करती थी।

- उदारीकरण ने **भारत को उच्च विकास दर प्राप्त करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत होने में मदद** की है।

- **नज्जीकरण (Privatization):**

- भारत ने सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में रहे **सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSEs)** का भी नज्जीकरण किया है।
- नज्जीकरण का उद्देश्य है सार्वजनिक उपकरणों की **दक्षता, लाभप्रदता एवं प्रतसिपर्द्धात्मकता** में सुधार करना; राजकोषीय बोझ कम

करना; और विकास के लिये संसाधनों का सृजन करना ।

- नज्जीकरण के विभिन्न रूप हो सकते हैं, जैसे वनिविश (नज्जी नविशकों को शेयर बेचना), रणनीतिक बिक्री (प्रबंधन नियंत्रण नज्जी खरीदारों को हस्तांतरित करना) या बंद करना (घाटे में चल रही इकाइयों को बंद करना) ।
- वर्ष 1991 के बाद से भारत ने 60 से अधिक सार्वजनिक उपकरणों का नज्जीकरण किया है, जिससे 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक जुटाये गए हैं ।

• वैश्वीकरण (Globalization):

- भारत ने भी वैश्वीकरण को भी अपनाया है, जिसका अर्थ है विश्व अर्थव्यवस्था के साथ अपने खुलेपन और एकीकरण को बढ़ाना ।
- वैश्वीकरण में व्यापार प्रवाह (नरियात एवं आयात), पूंजी प्रवाह (प्रत्यक्ष विदेशी नविश एवं पोर्टफोलियो नविश), प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (पेटेंट एवं लाइसेंस), और प्रवासन प्रवाह (कामगारों और छात्रों के रूप में) को बढ़ाना शामिल है ।
- वैश्वीकरण नए बाजारों तक पहुँच, सस्ते इनपुट, विदेशी मुद्रा, प्रौद्योगिकी और कौशल जैसे लाभ ला सकता है । हालाँकि यह प्रतस्पर्धा, अस्थिरता, निर्भरता और असमानता जैसी चुनौतियाँ भी उत्पन्न कर सकता है ।

• नई आर्थिक नीति (New Economic Policy):

- भारत ने कोविड-19 महामारी और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के जवाब में वर्ष 2020 में एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की ।
- इस नीति में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और खंडों को समर्थन प्रदान करने के लिये 20 लाख करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर) का प्रोत्साहन पैकेज शामिल है ।
- नीति में कृषि, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, खनन, बजिली और कराधान जैसे क्षेत्रों में सुधारों की एक शृंखला भी शामिल है ।

- इस नीति का लक्ष्य भारत को पोस्ट-कोविड विश्व में आत्मनिर्भर (self-reliant) और प्रत्यास्थ (resilient) बनाना है ।

• दवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code- IBC):

- यह कॉर्पोरेट देनदारों, वित्तीय ऋणदाताओं और परिचालन ऋणदाताओं के दवाला एवं शोधन अक्षमता के मामलों को हल करने के लिये एक समयबद्ध एवं बाजार-आधारित तंत्र प्रदान करता है ।
- इसका उद्देश्य परसिंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करना, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और कारोबार सुगमता (ease of doing business) में सुधार करना है ।

- भारतीय दवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 तक IBC के तहत 4541 कॉर्पोरेट दवाला समाधान प्रक्रियाएँ शुरू की गईं, जिनमें से 2029 मामलों का समाधान (resolution), परसिमापन (liquidation) या प्रत्याहरण (withdrawal) द्वारा सुलझा लिया गया है ।

• श्रम संहिता (Labour Codes):

- इनमें चार कोड या संहिताएँ शामिल हैं जिनका उद्देश्य केंद्रीय श्रम कानूनों को चार व्यापक श्रेणियों में समेकित एवं सरलीकृत करना है: वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा एवं व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य ।
- ये कोड नियोक्ताओं को कामगारों को नियोजित करने एवं कार्यमुक्त करने में लचीलापन प्रदान करने, व्यवसायों के लिये पंजीकरण एवं अनुपालन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, अनौपचारिक कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने और ट्रेड यूनियनों एवं सामूहिक सौदेबाजी की भूमिका को बढ़ावा देने की मंशा रखते हैं ।

• उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (Production-linked Incentive- PLI) योजना:

- भारत ने ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में वनिरिमाण एवं नरियात को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2020 में एक PLI योजना शुरू की ।
- यह योजना पात्र वनिरिमाताओं को पाँच वर्षों की अवधि में उनकी वृद्धशील बिक्री और नविश के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है ।

- इस योजना का कुल परवियय 1.46 लाख करोड़ रुपए है और इससे रोजगार सृजन, वदिशी नविश आकर्षति करने, प्रतसिप्रद्धात्मकता बढ़ाने और आयात नरिभरता कम होने की उम्मीद है ।

आर्थिक चुनौतियों से नपिटने के लयि कुछ सुझाव:

• उपभोग और नविश मांग को बढ़ावा देना:

- सरकार को अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों और खंडों को प्रत्यक्ष वत्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना चाहयि जो महामारी से बुरी तरह प्रभावति हुए हैं, जैसे कि **MSMEs, अनौपचारिक कामगार, ग्रामीण परिवार और नमिन-आय समूह** ।
- वत्तीय प्रोत्साहन का उद्देश्य उनकी आय, क्रय शक्ति और ऋण तक पहुँच को बढ़ाना होना चाहयि ।
- सरकार को सार्वजनिक अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा में भी नविश करना चाहयि, जसिसे रोजगार सृजति हो सकते हैं, उत्पादकता में सुधार हो सकता है और मानव पूंजी की वृद्धि हो सकती है ।

• नरियात प्रतसिप्रद्धात्मकता को बढ़ाना:

- सरकार को वत्तीय प्रोत्साहन, सबसिडी, कर छूट और अवसंरचना समर्थन प्रदान करने के माध्यम से वनिरिमाण, सेवाओं और कृषि जैसे नरियात-उन्मुख क्षेत्रों को बढ़ावा देना चाहयि ।
- सरकार को नए बाजारों तक पहुँच बनाने और अपनी नरियात टोकरी में वविधिता लाने के लयि **संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और आसियान** जैसे रणनीतिक भागीदारों के साथ व्यापार समझौते भी संपन्न करने चाहयि ।
- सरकार को गुणवत्ता मानक, लॉजिस्टिक्स लागत और व्यापार सुवधि के मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहयि जो भारत के नरियात प्रदर्शन को प्रभावति करते हैं ।

• वत्तीय क्षेत्र में सुधार:

- सरकार को **गैर-नषिपादति परसिंपत्तियों (NPAs)** की समस्या का समाधान करके, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्रूजिकरण, प्रशासन एवं वनियमन में सुधार और वत्तीय समावेशन एवं नवाचार को प्रोत्साहति करने के माध्यम से वत्तीय क्षेत्र को सुदृढ़ करना चाहयि ।
- सरकार को **बाण्ड बाजार, बीमा बाजार और पेंशन बाजार का विकास** भी करना चाहयि, जो अवसंरचना के लयि दीर्घकालिक वत्ति और वृद्धि जनों के लयि सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं ।

• व्यावसायिक माहौल में सुधार करना:

- सरकार को **लालफीताशाही, भ्रष्टाचार और नीतगित अनश्चितता को कम करके भारत में व्यापार करने के लयि नयामक ढाँचे को सरल बनाना** चाहयि ।

- सरकार को **श्रम कानूनों, भूमि अधग्रहण कानूनों, अनुबंध प्रवर्तन कानूनों और दवालियापन कानूनों में सुधारों को भी लागू करना चाहयि जो श्रम बाजार, भूमि बाजार, ऋण बाजार और कानूनी प्रणाली के लचीलेपन एवं दक्षता में सुधार कर सकते हैं ।**

• नवाचार और उद्यमता को बढ़ावा देना:

- सरकार को **अनुसंधान एवं विकास, वजिज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और इनक्यूबेटर्स का समर्थन करके भारत में नवाचार एवं उद्यमता** की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहयि ।
- सरकार को एक ऐसे पारस्थितिकी तंत्र के नरिमाण के लयि शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की सुवधि भी प्रदान करनी चाहयि जो नए वचारों, उत्पादों, प्रक्रयिओं और समाधानों का सृजन कर सके ।
- सरकार को बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा भी करनी चाहयि और पेटेंटगि एवं लाइसेंसगि को प्रोत्साहति करना चाहयि ।

• असमानता और गरीबी को संबोधति करना:

- सरकार को ऐसी प्रगतशील कराधान नीतियों को लागू करके भारत में असमानता और गरीबी को संबोधित करना चाहिये जो आय और धन को अमीरों से गरीबों की ओर पुनर्वितरित कर सके।
- सरकार को सामाजिक कल्याण योजनाओं के कवरेज और गुणवत्ता का भी विस्तार करना चाहिये जो **समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को बुनियादी आय सहायता, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा छात्रवृत्ति, आवास सब्सिडी** और कौशल विकास प्रदान कर सके।
- सरकार को महिलाओं, अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों और हाशिये पर स्थिति अनुभव समूहों को उनके लिये समान अधिकार, अवसर और आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित करके सशक्त बनाना चाहिये।

• **जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण को कम करना:**

- सरकार को जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण को कम करने के लिये हरित नीतियों अपनानी चाहिये जो **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (GHGs)** को कम कर सकती हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दे सकती हैं, ऊर्जा दक्षता बढ़ा सकती हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकती हैं, जैव विविधता की रक्षा कर सकती हैं और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार कर सकती हैं।
- सरकार को ऐसे अनुकूलन उपायों को भी लागू करना चाहिये जो बाढ़, सूखा, चक्रवात, ग्रीष्म लहर जैसे जलवायु आघातों के प्रति प्रत्यास्थता को बढ़ा सकें।

अभ्यास प्रश्न: मौजूदा आर्थिक चुनौतियों, आर्थिक सुधारों द्वारा प्रस्तुत अवसरों और उनके कार्यान्वयन से जुड़े सामंजस्य एवं जोखिमों का परीक्षण कीजिये।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा पछिले वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रलम्बित:

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है, जिसके द्वारा

1. किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी संचय कर पाते हैं।
2. देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है।
3. गोचर धन का संचय हो पाता है।
4. अगोचर धन का संचय हो पाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. 1 और 2
2. केवल 2
3. 2 और 4
4. 1, 3 और 4

उत्तर: C

मेन्स:

प्रश्न 1. भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप औपचारिक क्षेत्र में रोज़गार कैसे कम हुए? क्या बढ़ती हुई अनौपचारिकता देश के विकास के लिये हानिकारक है?

(2016)

